बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 171 ● नई दिल्ली ● सोमवार 07 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन बी-2/370, सुल्तानपुरी दिल्ली-86

समाज के हर तबके को जोड़कर आगे बढ़ने का माध्यम है सहकारिता मॉडल: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस समय की सभी सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाज के हर वर्ग को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ने की है। इसमें सहकारिता का मॉडल सरकारों को सबसे अधिक मूल्यवान सहयोग प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मॉडल का सदुपयोग करते हुए हर वर्ग को विकास का भागीदार बनाया चाहिए। सहकारिता के महत्त्व को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। सहकारिता पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सरकार को कहा कि भारत एक समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

दिल्ली में ईओएल वाहन नीति पर सवाल करते हुए एलजी वीके सक्सेना ने लिखा सीएम रेखा गुप्ता को पत्र

नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति हैं और पुराना वाहन यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर राजधानी में एंड ऑफ लाइफ (EOL) Vehicles, यानी 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर CAQM की नई गाइडलाइंस को लेकर गहरी चिंता जताई है। बता दें सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में पेट्रोल-डीजल न देने और वाहनों को स्क्रैप करने की बात कही गई है। उपराज्यपाल ने इस नीति की व्यावहारिकता, कानूनी वैधता और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। उपराज्यपाल ने पत्र में सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और केंद्र सरकार से बातचीत कर नियमों की समीक्षा की मांग करे. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने सार्वजनिक चर्चाओं, पर्यावरण मंत्री के पत्र और 3 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद गहराई से विचार किया है। चिट्ठी में उल्लेख किया गया है कि उन्हें नागरिकों, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों से बड़ी संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जो बताती हैं कि CAQM की हालिया गाइडलाइंस व्यावहारिक नहीं हैं और इनके पर्यावरणीय लाभ भी संदिग्ध हैं। एलजी सक्सेना ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 और हरित के 2014 के आदेशों में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने की बात की गई थी, लेकिन यह आदेश केंद्रीय मोटर वाहन

अधिनियम 1988 की धारा 59 की भावना से मेल नहीं खाता, जो पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि एक वाहन दिल्ली में 10 साल पुराना होकर अवैध हो जाता है, लेकिन वही वाहन मुंबई, चेन्नई या अहमदाबाद में वैध रूप से चल सकता है, तो यह तार्किक नहीं है। उपराज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि केवल उम्र के आधार पर किसी वाहन को एंड ऑफ लाइफ घोषित करना न केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अन्यायपूर्ण है, विशेषकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिनके लिए वाहन खरीदना एक बड़ा पूंजीगत निवेश होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बीएस-6 मानक वाले वाहन, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हैं और कम चले हैं, उन्हें भी कबाड़ के भाव बेचने को मजबूर किया जा रहा है। 5 पेज के इस पत्र में उपराज्यपाल ने यह भी लिखा कि दिल्ली के लोगों को उनके निवास के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता, जबकि पास के राज्यों में वही वाहन वैध हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से संपर्क कर Vehicle Scrapping Facility Rules, 2021 की समीक्षा की मांग करनी चाहिए और एक व्यावहारिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय परीक्षण के आधार पर तैयार किया गया फ्रेमवर्क लागू करना चाहिए, उन्होंने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सलाह दी है।

इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वायु प्रदूषण सिर्फ वाहनों से नहीं, बल्कि पराली, धूल, मौसम, निर्माण कार्य और ट्रैफिक जाम जैसी अनेक वजहों से होता है। ऐसे में सरकार को 3 महीने में एक समग्र वायु गुणवत्ता सुधार योजना तैयार करनी चाहिए और पुराने वाहनों को CNG या इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए जन-जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान शुरू करना चाहिए, पत्र के अंत में उपराज्यपाल ने कहा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर और साझा जिम्मेदारी है, लेकिन इससे निपटने के लिए कानूनी निष्पक्षता, सामाजिक संवेदनशीलता और व्यावहारिक सोच को बराबर महत्व देना आवश्यक है।

डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों खाली नहीं किया बंगला सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी पर पूर्व सीजेआई का पहला रिएक्शन

नई दिल्ली। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकारी आवास को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को लिखी गई चिट्ठी पर पहली प्रतिक्रिया दी है. पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने बंगला न खाली किए जाने को लेकर व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए जवाब दिया है. पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने बंगला खाली करने में हो रही देरी को लेकर कहा कि उनके परिवार की जरूरतों के चलते इसमें देरी हुई है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों को इसकी आवश्यकता है. पूर्व सीजेआई को 8 महीने बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिख कर चंद्रचूड़ से आवास खाली करवाने को कहा है.

बेटियों को है गंभीर बीमारी- चंद्रचूड़

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी बेटियां गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, जिनमें नेमालाइन मयोपैथी नाम की एक जेनेटिक बीमारी भी शामिल है. उनका इलाज दिल्ली के AIIMS अस्पताल में चल रहा है. इसी वजह से उनके लिए एक सही और सुविधाजनक घर ढूंढ़ना आसान नहीं था.

बंगले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट को पहले ही बताया

चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों और अफसरों को इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से अहसास है, क्योंकि वे देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर रह चुके हैं.

मरम्मत रुकी तो मांगा था थोड़ा और समय

रिटायर होने के बाद उन्हें तुगलक रोड पर नया बंगला मिला था, लेकिन उसमें मरम्मत का काम दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण नियमों के चलते रुक गया. इस वजह से उन्होंने पुराने बंगले में कुछ और समय तक रहने की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें मिल गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बंगला तुरंत खाली करने को कहा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आवास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5, जो मौजूदा सीजेआई के लिए तय है उसे तुरंत खाली कराया जाए. चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में रिटायर हुए थे, लेकिन अभी भी उसी बंगले में रह रहे हैं.

उनके बाद के दोनों सीजेआई अपने पुराने बंगलों में ही रह रहे हैं. चंद्रचूड़ ने आखिरी बार 31 मई 2025 तक रुकने की मौखिक मंजूरी ली थी, लेकिन अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

दिल्ली के लुटियंस जोन में 100 करोड़ का बंगला खरीदने वाले की कहानी, कांग्रेस नेता से भी है संबंध

नई दिल्ली । दिल्ली के सबसे पॉश और प्रतिष्ठित लुटियंस जोन में अब राजस्थान की एक रियासत का झंडा लहराएगा. अलवर के पूर्व राजघराने के सदस्य यशवंत सिंह ने दिल्ली के मशहूर गोल्फ लिंक्स इलाके में 100 करोड़ रुपये में एक शाही बंगला खरीदा है. ये सौदा राजधानी के हाई-प्रोफाइल प्रॉपर्टी बाजार में सुर्खियों का विषय बना हुआ है. इससे पहले यशवंत सिंह का निवास दिल्ली की औरंगजेब रोड पर था, जो कि कई बीघे में फैला था. बताया जा रहा है कि उम्र के इस पड़ाव (90 वर्ष से अधिक) में इतना बड़ा घर संभालना उनके लिए और परिवार के लिए कठिन हो गया था. इसी वजह से उन्होंने औरंगजेब रोड वाला बंगला बेचा और एक कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद कीमती घर गोल्फ लिंक्स में खरीद लिया. सूत्रों के मुताबिक, यशवंत सिंह ने ये बंगला डीएलएफ 'द कैमिलियाज से जुड़ी अनु जिंदल से खरीदा है. रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इस प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ रुपये तय हुई और इसके लिए 7 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी और निगम टैक्स जमा कराया गया है. गोल्फ लिंक्स स्थित यह बंगला 867 वर्गमीटर में फैला हुआ है, इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के साथ टैरेस पर एक बरसाती भी बनी है. इसके अलावा नौकरों के लिए सर्वेंट रूम जैसी व्यवस्थाएं भी हैं. परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक, अब यशवंत सिंह और उनका परिवार इस नए बंगले में जल्द ही शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है. खुद यशवंत सिंह अपने समय में टेनिस के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने अर्जुन अवार्ड एसोसिएशन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है. उनकी खेल परंपरा को उनके तीनों बच्चों ने भी आगे बढ़ाया. उनके बेटे और बेटियां स्क्वॉश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और भारत के लिए कई मेडल भी जीत चुके हैं. यशवंत सिंह, अलवर से कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र सिंह के सगे चाचा हैं. बता दें दिल्ली का लुटियंस जोन हमेशा से रुतबे और रसूख का प्रतीक रहा है. यहां की प्रॉपर्टी जब भी बिकती है, या खरीदी जाती है, तो वह चर्चा में आ जाती है. अब अलवर के राजपरिवार ने इस प्रतिष्ठित इलाके में अपने नए निवास का ऐलान कर दिया है.

नजफगढ़ में दोहरे हत्याकांड के चश्मदीद की दिनदहाड़े हत्या, गोलियों से कर दिया छलनी

नई दिल्ली। राजधानी में एक बार फिर अपराध की चिंगारी धधकने लगी है. गैंगवार का वह खौफनाक दौर, जिसे दिल्ली भूलने लगी थी, अब फिर से लौटता नजर आ रहा है. बवाना की वारदात को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि शुक्रवार शाम नजफगढ़ की सड़कों पर एक और सनसनीखेज शूटआउट ने राजधानी को दहला दिया. दिचाऊं पेट्रोल पंप के पास बाइक पर सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक कार को रोक कर 33 वर्षीय युवक नीरज तेहलान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई. जिससे नीरज की मौके पर ही मौत हो गई. गोलीबारी की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची नजफगढ़ थाना पुलिस ने नीरज को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार, नीरज नंगली सकरावती का रहने वाला था और वर्ष 2024 में नजफगढ़ के एक चर्चित सैलून दोहरे हत्याकांड का प्रमुख गवाह था. पुलिस को शक है कि इसी गवाही को रोकने के लिए उसे मौत के घाट उतारा गया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है. वारदात के तरीके और निशाने की सटीकता को देखते हुए पुलिस को इसमें किसी शातिर गिरोह के शामिल होने का संदेह है. बीते कुछ दिनों में गैंगवार की घटनाओं ने एक बार फिर दिल्ली के शांत होते माहौल में डर और असुरक्षा की लहर दौड़ा दी है.

पिछले 15 दिनों से मेरे घर में भी गंदा पानी आ रहा है : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली।

पूर्वी दिल्ली में सीवेज मिला गंदा पानी घरों में सप्लाई होने को लेकर कोर्ट से मिली डीजेबी को फटकार के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के चारों इंजन फेल हो चुके हैं. ये चारों इंजन मिलकर भी पांच महीने में दिल्ली को जनता को साफ पानी तक नहीं दे पाए. आज हालात ये है कि दिल्ली के जिन इलाकों में कभी गंदा पानी नहीं आता था, वहां भी गंदा पानी आ रहा है और लोगों को मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के मंत्री और विधायक तक नहीं सुन रहे हैं. लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है.आप के वरिष्ठ नेता व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को पानी के मुद्दे पर मीडिया बातचीत में कहा कि आज दिल्ली में लोगों को हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है क्योंकि ना तो बीजेपी के विधायक, ना बीजेपी सरकार के विभाग, ना मंत्री और ना मुख्यमंत्री सुन रही हैं. जिन इलाकों में कभी गंदा पानी नहीं आया, आज वहां गंदा पानी आ रहा है. मेरे अपने घर में 8 साल पहले हम लोगों ने पानी की लाइन बदलवाई. यहां तक कि पूरे इलाके की लाइन चेंज कराई. कभी गंदा पानी नहीं आया. मगर पिछले 15 दिनों से मेरे घर में भी गंदा पानी आ रहा है. सीवर का पानी आ रहा है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरीके की गंदी व्यवस्था और गंदी राजनीति है कि अगर कोई बीजेपी विधायक के कार्यालय में शिकायत करने जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि तुमने किसको वोट दिया तुम तो फलां पार्टी के हो. इस तरीके का दुर्व्यवहार जो दिल्ली की जनता के साथ किया जा रहा है, वह पहले कभी देखा नहीं गया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी तक जितने काम जनता को दिख रहे हैं, लगभग 95 फीसद काम पिछली आप सरकार ने सेंक्शन करके छोड़े थे. नए कामों की शुरुआत अभी भी नहीं हो पाई है, जबकि जल बोर्ड, सीवर और हमारे इलाके के काम मेरे द्वारा सेंक्शन किए गए थे, जिसके लिए मैंने विधायक निधि दी थी. नई सरकार के कामों में सुस्ती है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता विज्ञापन करना और हर चीज का ढिंढोरा पीटना है. बीजेपी सरकार अपनी बस नहीं लाई, पुरानी बसों पर उसने लीपापोती कर दी और दावा किया कि वह उनकी है. ऐसे ही बीजेपी अपना आरोग्य मंदिर नहीं बना पाई, पुराने मोहल्ला क्लीनिकों की लीपापोती कर दी और कह रहे हैं, अब ये हमारे हैं. सिर्फ लीपापोती करने से सरकारें नहीं चलतीं, काम करना पड़ेगा.

उदयपुर फाइल्स पर रोक की मांग, जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, नफरत फैलाने का आरोप

नई दिल्ली। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मौलाना अरशद मदनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे है. हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. फिल्म 11 जुलाई को विश्व स्तर पर रिलीज होने वाली है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म का ट्रेलर जो 26 जून को जारी हुआ वो समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाला है. देश में पहले से ही मौजूद धार्मिक तनाव को और भड़काने वाला है. याचिका के मुताबिक फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से जिस तरीके से सर्टिफिकेट दिया गया है. वह सिनेमा अधिनियम, 1952 की धारा 5बी और 1991 में बनाए गए फिल्म प्रमाणन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट [illegible] दी गई सर्टिफिकेशन को रद्द करे और फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाए. फिल्म कथित रूप से 2022 में उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है. लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें कोर्ट की कार्यवाही एक मुख्यमंत्री का पक्षपाती बयान और नूपुर शर्मा के दिए गए विवादास्पद बयान को दोहराया गया है. याचिका में कहा गया है कि यही बयान पहले भी देश में हिंसा और तनाव का कारण बने थे और अब फिल्म में उन्हीं बातों को दोहराकर सांप्रदायिक भावनाओं को फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है. कोर्ट में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म का ट्रेलर मुस्लिम समुदाय को एकतरफा और नकारात्मक तरीके से

प्रस्तुत करता है. जिससे समुदाय की गरिमा और जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है. ट्रेलर में कथित रूप से धार्मिक नेताओं को नाबालिग बच्चों के साथ आपत्तिजनक संबंधों में दिखाया गया है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक और उचित दृश्य नहीं है .याचिकाकर्ता के मुताबिक फिल्म में ज्ञानवापी मुद्दे को भी छेड़ा गया है जो वर्तमान में वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे विवादित मुद्दों का फिल्म के रूप में दिखाना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने और धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है. कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग इस तरह नहीं किया जा सकता है. जिससे समाज में नफरत फैले, भाईचारे पर आघात हो और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और समाज में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, विचारों और जीवनशैली के लोगों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व कमजोर हो. यह फिल्म न केवल सांप्रदायिक तनाव को हवा देती है बल्कि यह आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करती है. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह दलील दिया गया है कि CBFC ने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की और ऐसे दृश्य और डायलॉग को सर्टिफिकेट दे दिया जो सीधे तौर पर नफरत फैलाते है. ऐसे में कोर्ट को इस पर विचार करने की जरूरत है. सिनेमा अधिनियम की धारा 5बी के तहत ऐसे किसी भी दृश्य को सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता जो अश्लील, अनैतिक, या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो. साथ ही 1991 के दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी फिल्म ऐसा दृष्टिकोण न दिखाए जो सांप्रदायिक भावना या राष्ट्रविरोधी विचारों को बढ़ावा दे. याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि फिल्म की रिलीज को रोका जाए और CBFC से जारी सर्टिफिकेट को रद्द किया जाए, ताकि देश की शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनी रह सके. दिल्ली हाई कोर्ट जमीयत की तरफ से दाखिल अर्जी पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है.

बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ, ईसी के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अब तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महुआ मोइत्रा ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा कि वह निर्वाचन आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध करती है, जिसके तहत संविधान के विभिन्न प्रावधानों का कथित उल्लंघन करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है। याचिका के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में दायर वर्तमान रिट याचिका में भारत निर्वाचन आयोग के 24 जून को जारी आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। आदेश के तहत बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 21, 325, 328 व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। महुआ ने अपनी याचिका में कहा, अगर इस आदेश को रद्द नहीं किया गया, तो यह देश में बड़े पैमाने पर पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है, जिससे लोकतंत्र, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कमजोर हो सकते हैं। महुआ ने शीर्ष अदालत से भारत निर्वाचन आयोग को देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण के इस तरह के आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अधिवक्ता नेहा राठी के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में कहा गया, देश में यह पहली बार है कि ईसीआई द्वारा इस तरह का अभ्यास किया जा रहा है, जहां उन मतदाताओं से अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में हैं या पहले भी कई बार मतदान कर चुके हैं। यह आवश्यकता अनुच्छेद 326 के विपरीत है और संविधान के आरपी अधिनियम 1950 द्वारा परिकल्पित नहीं की गई बाहरी योग्यताएं पेश करती है। बता दें कि इस मामले में गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ने भी एक याचिका दायर कर चुका है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई है।चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिला राहत

नई दिल्ली । दिल्ली में मानसून का असर दिखने लगा है। आज दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। दिल्ली के फिरोजशाह रोड समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 5 से 9 जुलाई तक दिल्ली में बारिश होने की बात कही थी। मौसम विभाग के अनुसार, 6, 7, 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 6, 7, 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में विभिन्न इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें देखी जा सकती है। ऐसे में 6, 7, 8 और 9 जुलाई को अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। बता दें कि देश के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में जहां मानसूनी वर्षा बड़ी राहत लेकर आ रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में यह आफत बनकर बरस रही है। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को हुई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दीं। 20 जून से 4 जुलाई के बीच 15 दिनों में ही दोनों राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और वर्षा जनित सड़क व अन्य हादसों में मरने वालों की संख्या 77 तक पहुंच गई है। इसमें हिमाचल में 75 और उत्तराखंड में 2 मौतें शामिल हैं। 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 30 से अधिक अभी लापता हैं। आईएमडी ने रविवार को भी भारी बारिश को लेकर 15 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, गोवा व कोंकण, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सिक्किम को छोड़कर पूर्वी समेत देश के अन्य हिस्सों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में मानसून के आगमन से लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 89 दर्ज किया गया जो संतोषजनक श्रेणी है। इसमें शुक्रवार की तुलना में 11 सूचकांक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान है कि सोमवार तक हवा संतोषजनक श्रेणी में बरकरार रहेगी। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 95 दर्ज किया गया। वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में एक्यूआई सबसे कम 77 एक्यूआई रहा।

मेट्रो में युवती ने पार की बेशर्मी की हदें, किया ऐसा अश्लील डांस देखकर लोग हुए शर्मसार

नई दिल्ली। सोशल मीडिया की इस दुनिया में कौन, कब, कहां और कैसे वायरल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अब जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें मेट्रो का शांत माहौल अचानक एक डांस फ्लोर में तब्दील हो जाता है। ट्रेन की रफ्तार के साथ ताल में थिरकती एक लड़की अपने वेस्टर्न और भड़कीले लिबास में ऐसा डांस करती है कि यात्रियों की नजरें तो ठहरती नहीं लेकिन हिम्मत भी किसी की नहीं होती कि उसे टोक सके। वायरल हो चुके इस वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। कोई इसे हिम्मत कह रहा है तो कोई बेशर्मी लेकिन तमाशा सब चुपचाप देख रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की नाकामी उजागर!

अनिल जैन

अब यह साफ हो गया है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अनावश्यक रूप से सच्चाई छुपा रही है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में कहा कि भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे। उनका कहना था कि कितने विमान गिरे यह मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि क्यों गिरे? अब उस क्यों गिरे का जवाब दिया है कि इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने। उन्होंने जकार्ता में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व का निर्देश था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाना है। इसलिए भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और इस वजह से पाकिस्तान को मौका मिला कि उसने भारत के विमानों को मार गिराया। यह बयान दो बिंदुओं पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। पहला तो यही कि भारत को लड़ाकू विमान गंवाने पड़े। दूसरा यह कि सेना के हाथ उस हद तक नहीं खुले हुए थे, जैसा कि सरकार ऐलान करती रही है। पता नहीं कैसे भारत के राजनीतिक नेतृत्व को यह भरोसा था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे तो वह भारत के अपनी सीमा में उड़ रहे विमानों को निशाना नहीं बनाएगा! यह समझदारी और खुफिया सूचना दोनों की विफलता है। अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान तैयार था और जैसे ही भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया उसने भारत की सीमा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को निशाना बना दिया। दुनिया में कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी बता दे तो भारत सरकार जज्बाती हो जाती है। भारत का चुनाव आयोग तो लड़ने मरने पर उतारू हो जाता है। पिछले दिनों तो चुनाव आयोग ने अमेरिका की इंटेलिजेंस नेटवर्क की प्रमुख को कह दिया था कि उनके यहां की ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन भारत की नहीं हो सकती। बहरहाल, भारत सरकार जैसे ईवीएम को लेकर जज्बाती हो जाती है वैसे ही वह कोविड वैक्सीन को लेकर भी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोविड वैक्सीन ने भारत सरकार को अपना ब्रांड एंबेसेडर या अपना वकील नियुक्त किया है।अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और एम्स दोनों ने कहा है कि इन दिनों अचानक बढ़े दिल के दौरों में वैक्सीन की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि वैक्सीन की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ है, जो लोग चलते फिरते गिर कर मरने लगे हैं या 20, 25 और 30 साल के पूरी तरह से स्वस्थ युवाओं को दिल का दौरा पड़ने लगा है! ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी तो पता लगाना चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया मान रही है कि वैक्सीन के साइड इफैक्ट्स हुए हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला है कि मोटे और मधुमेह के मरीजों के शरीर में वैक्सीन की वजह से सूजन और रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसे कई और शोध हुए हैं, जिनसे वैक्सीन के साइड इफैक्ट्स का पता चला है। कई वैक्सीन कंपनियों ने भी इसे स्वीकार किया है। लेकिन भारत सरकार ने अपनी ओर से सारी वैक्सीन को क्लीन चिट दे दी है।

खरगे ने क्या संदेश दिया?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले दिनों कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस बारे में फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। उनके इस बयान पर भाजपा के कई नेताओं ने तंज करते हुए कहा कि खरगे सिर्फ दिखावे के लिए अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का असली आलाकमान तो गांधी परिवार है। हालांकि कांग्रेस नेताओं के लिए इसका जवाब देना बहुत आसान है। वे भाजपा नेताओं से पूछ सकते हैं कि क्या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के आलाकमान हैं? सबको पता है कि भाजपा में आलाकमान का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। जैसे नड्डा भाजपा के आलाकमान नहीं है वैसे ही खरगे भी कांग्रेस के आलाकमान नहीं है। लेकिन सवाल है कि खरगे ने यह बात क्यों कही? उन्हें भी पता रहा होगा कि अगर वे कहेंगे कि मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान करेगा तो उनकी अथॉरिटी को लेकर सवाल उठेगा। फिर भी उन्होंने यह बात कही। जाहिर है कि वे कोई संदेश देना चाहते थे। एक संदेश तो यह कि वे पार्टी में जो कुछ चल रहा है, उससे वे नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक सारे फैसले राहुल गांधी की ओर से केसी वेणुगोपाल करते हैं। दूसरा संदेश दूर की कौड़ी है। कहा जा रहा है कि फैसला खुद खरगे के बारे में होना है इसलिए उन्होंने कहा कि आलाकमान फैसला करेगा। गौरतलब है कि खरगे की पुरानी इच्छा कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरी ढाई साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा होता है तो सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों चुप रह सकते हैं। लेकिन तब सवाल है कि अध्यक्ष कौन बनेगा? शिवकुमार को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

दोपहिया वाहनों पर टोल की खबर कहां से आई?

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में अचानक यह खबर आई और वायरल हो गई कि अब नेशनल हाईवे पर दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा। ऐसा लगा, जैसे सचमुच सरकार ने इसका फैसला कर लिया है और उसके बाद सूत्रों हवाले से खबर जारी की गई है। लेकिन चार-पांच घंटे के बाद इस खबर का खंडन आ गया। सरकार की ओर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इसका खंडन किया। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाल कर कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अब सवाल है कि ऐसी खबर कहां से आई? क्या सरकार में किसी स्तर पर इसकी चर्चा हुई थी, जहां से खबर लीक हुई? इसी तरह कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूपीआई से होने वाले भुगतान पर सरकार शुल्क लगाएगी। संभावित शुल्क का ढांचा भी जारी कर दिया गया था। यह खबर भी कई घंटे तक चलती रही और फिर सरकार की ओर से इसका भी खंडन किया गया। इस तरह की खबरें चलना और उसके बाद उनका खंडन आना संदेह पैदा करता है कि कहीं सरकार कोई प्रयोग तो नहीं कर रही है? अगर विपक्ष या उसके इकोसिस्टम के लोग सरकार को बदनाम कराने वाली इस तरह की अफवाहें फैला रहे होते तो सरकार की ओर से निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया जाता और कोई न कोई कार्रवाई होती। लेकिन दोनों मामलों में कोई भी कार्रवाई होने की खबर नहीं है।

ब्लैक बॉक्स का डाटा विश्लेषण कब होगा?

अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को तीन हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स के डाटा का विश्लेषण नहीं हुआ है। पहले खबर आई थी कि आग लगने की वजह से विमान का ब्लैक बॉक्स डैमेज हुआ है और उसका डाटा रिकवर करने के लिए उसे अमेरिका भेजा जाएगा। यह खबर आने के बाद से सरकार इसका खंडन करने में लगी है। कहा जा रहा है कि भारत में डाटा रिकवर कर लिया गया है और अब उसका विश्लेषण किया जाएगा। टुकड़ों-टुकड़ों में खबरें दी जा रही है कि डाटा का विश्लेषण होने में 10 दिन का समय लगेगा। सवाल है कि अगर डाटा का विश्लेषण नहीं हुआ है तो हादसे के बारे में एक-एक करके खबरें कहां से आ रही हैं? हादसे के 18 दिन के बाद नागरिक विमानन राज्य मंत्री ने एक निजी टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में कहा कि सरकार साजिश के पहलू से भी इसकी जांच कराएगी। निश्चित रूप से हर पहलू से हादसे की जांच होनी चाहिए क्योंकि यह कोई मामूली हादसा नहीं है।

बिहार: 'वक़्फ़ तो बहाना है, संविधान निशाना है'

यह कानून असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी है। यह हमारे धार्मिक स्थलों और विरासत भवनों को छीनने का प्रयास है। जब तक केंद्र की सरकार वक्फ का यह काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक यह संघर्ष जारी रखेंगे। यह कथन इमारते-शरिया के ओहदेदार का है। लेकिन इन बातों के मनोभावों से कहीं अधिक क्षोभ के मनोभाव परिलक्षित हो रहे थे, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटे हजारों हज़ार की संख्या में जुटे लोगों के चेहरों से। जो वहां पहुंचे थे केंद्र की मौजूदा सरकार द्वारा वक्फ़ संशोधन की आड़ में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला किये जाने के विरोध में पहुंचे थे। 29 जून को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'इमारते शरिया' और 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' समेत कई अन्य सामाजिक जन संगठनों के आह्वान पर 'वक्फ़ बचाओ, संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसमें बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल,ओडिशा व झारखंड समेत कई अन्य राज्यों से मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। चर्चा है कि बिहार व पटना गांधी मैदान के हालिया दस वर्षों के इतिहास में इतना विशाल जन जुटान-प्रदर्शन नहीं हुआ था। अमूमन पूरे गांधी मैदान के चप्पे चप्पे में उपस्थित प्रदर्शनकारियों की अनगिन तादाद दिखला रही थी कि -वक्फ़ संशोधन- की आड़ में केंद्र की मौजूदा सरकार द्वारा वक्फ़ की अकूत संपत्तियों को हड़पने की कोई भी साजिश नहीं चलने दी जाएगी। तीखी गर्मी और उमस के बावजूद कार्यक्रम के मंच से लेकर दूर दूर तक खचाखच भरे लोगों और खासकर युवाओं की सरगर्मी पूरे शबाब पर थी, जो मंच से वक्ताओं के भाषणों के समर्थन में जोशो-खरोश के साथ तालियों और नारों से प्रदर्शित हो रही थी। कार्यक्रम को आयोजक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा बिहार इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी द्वारा भेजे गए सन्देश को पढ़कर सुनाया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि- पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि देश की आज़ादी की लड़ाई कैसे हम सबों ने मिलकर लड़ी है। सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानियां दी है। देश किसी अकेले का नहीं है। ऐसे में कोई सरकार यदि देश में नफ़रत और लोगों को बांटने की राजनीति करके अपना राज चलाना चाहेगी तो देश की जनता उसे नहीं चलने देगी। बिहार में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम भाजपा सरकार के 'वक्फ़ संशोधन' काला कानून को किसी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये लड़ाई हम सबकी साझी लड़ाई है। अभी हमारे सामने बिहार का विधान सभा चुनाव है और जरूरत है कि इस चुनाव में संविधान विरोधी लोगों और नफ़रत फैलाने वालों को पहले बिहार की सत्ता से बाहर करना होगा। उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट जज ने जब पूछा कि क्या इसके बाद चर्च, गुरुद्वारे और हिन्दुओं के मंदिरों के लिए भी कानून बनेंगे तो सरकार का वकील कुछ नहीं बोल पाया। दीपंकर ने इस दौरान केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाये जाने का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि हर दिन देश के संविधान की दुहाई देने वाली भाजपा सरकार और मोदी जी समेत उसके सारे नेता, आज गरीबों के वोट देने के संविधानिक अधिकार को ही खत्म करने पर आमादा हैं। जिसे एकजुट विरोध से ही रोका जा सकता है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज़ में कहा कि वक्फ़ बिल मुसलमानों के लिए उसी तरह है बर्बादी का सामान है कि- हमीं को कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। यह बिल मुसलमानों को मंजूर नहीं है। माले बिहार विधायक दल नेता महबूब आलम ने कहा कि ऊपर से देखने में -वक्फ़ संशोधन कानून- के जरिये मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान तो बहाना है, संविधान पर निशाना है। यह सवाल अवाम और गरीब गुरबों का सवाल है। भाजपा जो देश बांटने की साजिश कर रही है, हम एकजुट होकर ही नाकाम किया जा सकता है। वीआईपी नेता मुकेश ने कहा कि भाजपा के नीयत में है गरीबों के अधिकारों को छीनना। इस काले कानून से न सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों को कम करने की कोशिश की जा रही है बल्कि इबादतगाहों और मुसलमानों की विरासत को लूटने की कोशिश है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुसलमान के नाम पर सनातन संस्कृति थोपने की साजिश है। जिसे इस राज्य की जनता कभी नहीं चलने देगी। कार्यक्रम को राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, राज्य सभा सदस्य संजय यादव, जहानाबाद सांसद सुरेन्द्र यादव तथा माले विधायक गोपाल रविदास के अलावा इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया और वक्फ़ संशोधन कानून को तत्काल रद्द करने की मांग की। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यधारा की मीडिया में अधिकांश का साम्प्रदायिक नजरिया एक बार फिर खुलकर सामने आ गया कि हजारों हजार की संगठित जनभागीदारी वाले कार्यक्रम की खबर को लगभग दबा दिया गया। किसी अखबार में खबर छपी भी तो बिलकुल अन्दर के पन्नों में।

भारत, चीन और पाकिस्तान

इसमें किसी प्रकार से कहीं भी कोई शंका नहीं हो सकती कि ऑपरेशन सिन्दूर के तहत चली चार दिन की सक्षिप्त लड़ाई में भारतीय फौजों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिये थे। इससे घबरा कर ही पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम की याचना की थी। विगत 7 से 10 मई तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ चीन ने इस प्रकार दिया कि उसके द्वारा पाकिस्तान को दी गई युद्ध सामग्री का भी परीक्षण हो गया। पाकिस्तान 81 प्रतिशत के लगभग अपनी जरूरत की आयुध सामग्री चीन से लेता है जिनमें लड़ाकू जहाज तक शामिल हैं। इसके साथ ही तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोनों की सप्लाई जमकर की और उन्हें चलाने वाले विशेषज्ञ भी सुलभ कराये। इस प्रकार भारत ने यह युद्ध तीन देशों के खिलाफ लड़ा जिसमें वह विजयी रहा और उसने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया जिसमें कुछ सैनिक अड्डे भी ऑपरेशन सिन्दूर की जद में आये। भारत की थल सेना के उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कल दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में इसी तथ्य का खुलासा किया है। उनके कथन से यह साफ हो गया कि चीन पाकिस्तान के कन्धे पर बन्दूक रख कर भारत को निशाना बना रहा था। जहां तक तुर्की का सवाल है तो इस्लामी देश होने की वजह से इसने पाकिस्तान का साथ देना बेहतर समझा हालांकि दशकों पूर्व में तुर्की भारत का समर्थक देश रहा है मगर इस देश में जब से इस्लामी कट्टरपंथी सक्रिय हुए हैं तब से इसके रुख में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। नहीं भूला जाना चाहिए कि यह मुस्तफा कमाल अतातुर्क का देश है जिन्होंने तुर्की को आधुनिक व वैज्ञानिक सोच वाला देश बनाने के लिए कड़ा संघर्ष पिछली सदी के तीसरे दशक में किया था। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद कमाल अतातुर्क ने तुर्की को धर्म निरपेक्ष देश बनाया था और अपने देश में मस्जिदों के स्थान पर शिक्षा संस्थान स्थापित कराये थे। मगर दूसरी तरफ चीन ऐसा देश है जिसकी निगाह 1949 में स्वतन्त्र होते ही तिब्बत पर थी और भारत के साथ सीमा विवाद पर उसका नजरिया विस्तारवादी था। पचास के दशक में पं. जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल के दौरान जब चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाई भारत की राजकीय यात्रा पर आये थे तो हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे लगे थे। मगर 1962 में इसकी विस्तारवादी नीयत साफ निकल कर बाहर आ गई और इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। तब इसकी फौजें असम के तेजपुर तक आ गई थीं। चीन ने तब भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए अचानक हमला किया था। चीन से दोस्ती के सबसे बड़े अलम्बरदार पं. जवाहर लाल नेहरू यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। चीन के बारे में युद्ध के समय पं. नेहरू ने भारत की संसद में कहा था कि चीन की मानसिकता युद्ध या लड़ाकू किस्म (मिलिट्री माइंडेड) की है। मगर पं. नेहरू गलती कर गये थे क्योंकि 1959 में ही चीन ने पूरे तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया था और यहां के लोगों पर साम्यवाद थोप दिया था। इसके बावजूद भारत ने 2003 तक तिब्बत को कभी चीन का अंग स्वीकार नहीं किया। यह कार्य 2003 में केन्द्र की सत्ता पर काबिज वाजपेयी सरकार ने किया और तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार कर लिया।

सम्पादकीय...

अनुशासित बनें

यह सच है कि दिल्ली एक प्रगतिशील राजधानी है जो देश की शान है लेकिन वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या के बीच दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते वाहन, जगह-जगह जाम एक खास संदेश दे रहे हैं जिसे सुनना और समझना होगा। इतना ही नहीं उपाय भी करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के नक्शे में एक खास पहचान रखती है जिसमें सम्पूर्ण भारत की विविधता का दीदार है लेकिन चिंतनीय बात बढ़ता ट्रैफिक तथा बढ़ते वाहन हैं। दिल्ली ने उन्नति के नए शिखर छुए हैं लेकिन आज की तारीख में वाहनों के मामले में जो विकराल समस्या उभर रही है वह सचमुच अलार्म दे रही है। वहीं बढ़ता वायु प्रदूषण भी एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। खुद को एक आधुनिकतम राजधानी के रूप में भी स्थापित किया है लेकिन वाहनों की बढ़ती संख्या एक नई चुनौती के रूप में ऊभर रहे हैं। बढ़ते वाहन वायु प्रदूषण की एक नई समस्या को भी जन्म दे रहे हैं जिसके लिए सरकारें गंभीरतापूर्वक बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि लोगों को खुद को इस मामले में अनुशासित बनना होगा। एक अनुमान के अनुसार पिछले तीन दशकों में दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या में लगभग 21 गुना वृद्धि हुई है, जबकि सड़क की लंबाई केवल दोगुनी हुई है। व्हीकल पर एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दिल्ली में सभी कैटेगरीज के 1.22 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड व्हीकल थे। रिपोर्ट के अनुसार 1981 से 2021 तक तीन दशक के बीच मोटर व्हीकल्स की तादाद में रिकार्ड तोड़ वृद्धि चिंतनीय है। वहीं इसी टाइम पीरियड में सड़क की लंबाई 15,487 किमी से बढ़कर महज 33,198 किमी हो सकी है। गाड़ियों की संख्या से बढ़े एक्सीडेंट्स राजधानी की सड़कों पर लगातार बढ़ती भीड़ ने कई परिवहन समस्याओं में खुद को प्रकट किया है। मेन रोड का ट्रैफिक सड़कों की वहन क्षमता की दहलीज को लगभग पार कर गया है। बढ़ती आबादी और सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। व्हीकल पॉपुलेशन, मानव व्यवहार भी मायने रखते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने भी स्वीकार किया कि दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर 1981 से 2021 के बीच 40 साल में दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या 21 गुना बढ़ी है। लेकिन बुनियादी सड़क ढांचा केवल दोगुना ही हो पाया है। यही असंतुलन हमारे शहरों का दम घोंट रहा है। इसके लिए महज तकनीक पर्याप्त नहीं है, व्यवहार परिवर्तन भी उतने ही आवश्यक हैं। हमें ई-वाहनों का भी इस्तेमाल करना होगा। लोग भी आज ई वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम है। ई वाहनों को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। दिल्ली की बसों में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत हो गई है। इसमें 7,600 से अधिक ई-बसें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। बताया जाता है कि दिल्ली हर साल तीन महीने के लिए रहने लायक नहीं रहती। वायु प्रदूषण से हमें 6.3 वर्ष की आयु हानि और लगभग 100,000 करोड़ यानी जीडीपी का तीन प्रतिशत का नुकसान होता है। सभी दो और तिपहिया वाहन एक वर्ष के भीतर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे तो अच्छा है। सभी नई टैक्सियां इलेक्ट्रिक वाली होनी चाहिए। यह तथ्य भी देखना जरूरी है कि राजधानी में करीब 90 लाख वाहन पंजीकृत हैं और एक अनुमान के अनुसार उनमें से करीब 50 लाख वाहन रोजाना सड़कों पर उतरते हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख वाहन पड़ोसी राज्य से राजधानी में आते हैं। इस तरह रोजाना राजधानी की सड़कों पर करीब 60 लाख वाहन दौड़ते हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था भी जरूरी है। राजधानी में पार्किंग की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। राजधानी में जिस रफ्तार से वाहनों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से पार्किंग की सुविधा नहीं हो रही है। रोजाना सड़कों पर उतरने वाले वाहनों की तुलना में पार्किंग व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस कारण पार्किंग को लेकर लोगों में आए दिन झगड़े होने के मामले सामने आते रहते हैं। इसके अलावा रोजाना सड़कों पर वाहन खड़े होने से यातायात जाम की समस्या बनी रहती है। लिहाजा राजधानी वर्तमान समय के दौरान पार्किंग सुविधा के मामले में एक बड़े संकट का सामना कर रही है। दिल्ली में लगभग 560 पार्किंग स्थल हैं और उनमें करीब 30 हजार वाहन खड़े हो सकते हैं। यह स्थिति एक गंभीर समस्या है, क्योंकि पार्किंग की कमी वाहन वालों के लिए एक चुनौती बन गई है। पार्किंग की कमी के कारण जब वाहन वालों को सड़कों पर या फिर अवैध स्थानों पर पार्किंग करनी पड़ती है। इससे न केवल यातायात में बाधा आती है और अधिक भीड़भाड़ होती है, बल्कि इससे सड़क सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इसके अलावा वाहन वालों का रोजाना पार्किंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनके समय की बर्बादी होती है। हालांकि सरकारी तौर पर पार्किंग समस्या दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन खुद गम्भीर नहीं हैं। वाहन पार्क करने की वो सेंस नहीं है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सड़कों के आस-पास गाड़ी पार्क करना ठीक बात नहीं। लोगों को अनुशासित बनना ही होगा। पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए स्थानीय निकायों ने कई बार पार्किंगस्थलों की संख्या में वृद्धि की है, लेकिन यह वृद्धि वाहन की बढ़ती संख्या के मुकाबले कहीं अधिक कम है। आखिरकार सड़कें और स्पेस तो उतना ही है। दिल्ली का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहा है। फ्लाई ओवरों का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में रिकार्ड बताते हैं कि दिल्ली में हर साल 7 से 9 लाख वाहन रजिस्टर्ड होते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 2000-3000 नए वाहन दिल्ली की सड़कों पर आते हैं। देखने में आया है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से आज भी दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शत-प्रतिशत रूप से जुड़ नहीं पाया। लोग अपनी कारों से आना-जाना पसंद करते हैं और यह एक स्टेटस सिंबल बन रहा है। महंगी कारें रखना शान बन गया है। एक-एक घर में तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच वाहन हैं। व्यापारी और कम्पनी लोगों के लिए यह ठीक हो सकता है लेकिन मोहल्ले कालोनियों में यह प्रवृत्ति ठीक नहीं।

सेकुलर और सोशलिस्ट को लेकर सियासी रार

उमेश चतुर्वेदी ।

इतिहास ने जब किसी कालखंड को काला अध्याय के रूप में स्वीकार कर लिया हो, तब उस कालखंड में लिए गए निर्णयों को वैधानिक कैसे माना जा सकता है। आपातकाल स्वाधीन भारत की तवारीख का काला दौर ही है। उसी दौर में संवैधानिक संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में 'सेक्युलर' और 'समाजवादी' शब्द जोड़ गए। ऐसे में इन शब्दों को हटाने की मांग पर विमर्श होना चाहिए, लेकिन हो रहा है विवाद। इसकी वजह यह है कि यह मांग खुलेतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। संघ की ऐसी आवाजें गैर बीजेपी दलों को अक्सर चुभती रही हैं। कांग्रेस ने इस बहाने संघ पर अपना पुराना आरोप दोहराना शुरू कर दिया, कि संघ और बीजेपी संविधान को बदलने की कोशिश में है। दिलचस्प यह है कि आपातकाल में कांग्रेसी अत्याचारों के शिकार हुए समाजवादी धड़े के दल भी संघ विरोध में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस बारे में क्या कहा है। आपातकाल की पचासवीं बरसी पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। ये शब्द पहले नहीं थे। बाद में इन्हें निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये शब्द संविधान में रहना चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए।' जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में आई है, तभी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक रट लगाए हुए हैं कि बीजेपी और संघ संविधान बदलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उनकी अगुआई में समूचे विपक्ष ने इसे बार-बार दोहराया। नई लोकसभा के गठन के दौरान विपक्षी सांसदों ने शपथ लेते वक्त अपने हाथ में संविधान की प्रति थामे रखी। अंतर बस यह रहा कि कांग्रेसी सांसदों के हाथ में लाल रंग के कवर वाली संविधान की प्रति रही तो दूसरे दलों के सांसदों के हाथों में नीले रंग के कवर वाली संविधान की प्रति रही। शपथ लेते वक्त भी विपक्षी सांसदों ने देश को संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और वे इसे बदलने नहीं देंगे। दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद एक बार भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ऐसी ही बयानबाजी में मशगूल हो गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। इसी के साथ लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पांच की बजाय छह साल कर दिया गया था। 1977 के आम चुनावों के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के जरिए आपातकाल के दौरान किए गए संवैधानिक बदलावों को बदल दिया। जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल को फिर से पांच साल करना शामिल था। लेकिन संविधान की प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'समाजवादी' शब्दों को हटाने का प्रयास नहीं हुआ। संघ की मांग का आधार मूल संविधान की प्रस्तावना है। जिसमें ये दोनों शब्द शामिल नहीं किए गए थे। ऐसा नहीं कि ऐसा करने की मांग नहीं हुई थी। संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने 15 नवंबर 1948 को संविधान के मसौदे में संशोधन प्रस्ताव रखते हुए भारत को 'धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी राज्यों का संघ' बनाने मांग की। लेकिन अंबेडकर ने इसे खारिज कर दिया। तब अंबेडकर ने कहा था, -राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय लोगों को समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं करना चाहिए। अंबेडकर का मानना था कि अगर संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ दिया जाता है तो यह भावी पीढ़ियों को उनका रास्ता चुनने की स्वतंत्रता को सीमित करेगा। उन्होंने कहा, इसे संविधान में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। नेहरू की भी सोच थी कि भारतीय संविधान का चरित्र ही धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए उसकी प्रस्तावना में इसे अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हो या फिर दूसरे विपक्षी दल, उन्हें आज के दौर में जब भी बीजेपी पर हमला या फिर संघ को कठघरे में खड़ा करना होता है, वे अंबेडकर के संविधान को याद करने लगते हैं। अंबेडकर के मूल्यों की रक्षा की बात करने लगते हैं। ऐसे में उनके सामने यह सवाल जरूर उठता है कि क्या आपातकाल थोपा जाना अंबेडकर के विचारों का सम्मान था और अगर वह नहीं था तो फिर सेकुलर और समाजवादी शब्दों का प्रस्तावना में शामिल होना सही कैसे है? एक और सवाल यह है कि जब आपातकाल ही नाजायज और अवैधानिक था तो फिर उस दौरान उठाए गए किसी कदम को जायज और संवैधानिक कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सवाल यह भी है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा ही कार्यपालिका हो गई थीं, जिनके सामने न्यायपालिका और विधायिका एक तरह से अधिकारहीन हो चुकी थी, तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय सही कैसे हो सकते हैं? संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए इन शब्दों की एक सीमा यह भी है कि इनकी कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए जिसकी जैसी सोच होती है, इनकी व्याख्या कर डालता है। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है कि संविधान की बुनियादी आत्मा को नहीं बदला जा सकता। इस नजरिए से भी देखें तो प्रस्तावना में जोड़े गए ये दोनों ही शब्द सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ठीक उलट हैं। इन दोनों शब्दों के जोड़े जाने के बाद ही संविधान का अलग ही रूप और चरित्र दिखने लगा है। जिसके आधार पर ज्यादातर कार्यपालिका और विधायिका फैसले लेने लगी है। कुछ जानकार तो मानते हैं कि कई सामाजिक समस्याओं की वजह ये दोनों शब्द ही हैं। जिनके चलते संवैधानिक संस्थाएं भारत के बुनियादी चरित्र के उलट कदम उठाती रही हैं या फैसले लेती रही है। अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देने में इन दोनों शब्दों का योगदान सबसे ज्यादा है। इन्हीं शब्दों के चलते तुष्टिकरण की राजनीति को भी बढ़ावा मिला है। इन शब्दों से मिले कवच की वजह से विखंडनकारी तत्व हावी हुए है, जो लगातार भारतीय समाज के बिखराव को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रस्तावना में आए बदलावों ने शासन के चरित्र को ही नहीं, प्रशासन की सोच को भी बदला है। लेकिन कभी इस नजरिए से इन शब्दों की सीमा को मापने और उनके असर को पहचानने की कोशिश नहीं हुई। कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस संघ की इस अपील को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ जरूर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरह आक्रामक मुद्रा में नहीं है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी और संघ आपातकाल के लिए लगातार कांग्रेस से माफी की मांग भी कर रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी आपातकाल के पीड़ित हैं और उन दिनों वे बीजेपी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ थे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में ही उन्होंने छपरा से लोकसभा का चुनाव जीता था। ऐसे में उनके लिए आपातकाल के मुद्दे पर देर तक कांग्रेस का साथ देना आसान नहीं होगा। लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि इस मुद्दे को कांग्रेस उठाए और पीछे से उसका साथ वे देते रहें। इस रणनीति के जरिए उनकी कोशिश है कि बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन से सत्ता छीन लें। लेकिन संघ इस मांग से उस तरह पीछे हटता नहीं दिख रहा, जिस तरह 2015 के चुनावों के दौरान आरक्षण पर आए मोहन भागवत के बयान से उपजे विवाद के चलते पीछे हटता दिखा। कांग्रेस ने अब तक आपातकाल को लेकर अपनी गलती नहीं मानी है। संघ की मांग के चलते यह मुद्दा उछल रहा है। जैसे-जैसे इस मुद्दे की तासीर बढ़ेगी, वैसे-वैसे कांग्रेस के लिए अपना बचाव कर पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि वह कैसे साबित कर पाएगी कि आपातकाल सही था? अगर वह आपातकाल को सही नहीं ठहरा पाएगी तो वह किस तरह साबित करेगी कि प्रस्तावना में किया गया बदलाव सही था। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है। चूंकि संघ के पास सीधे तौर पर कोई वैधानिक ताकत नहीं है लेकिन विमर्श के बहाने वह इन शब्दों के औचित्य के साथ ही कांग्रेस की तब की करतूत की याद को जीवंत बनाए रखना चाहता है। इसके जरिए निश्चित तौर पर एक ऐसा लोकमानस बनेगा।

> बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ जरूर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरह आक्रामक मुद्रा में नहीं है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी और संघ आपातकाल के लिए लगातार कांग्रेस से माफी की मांग भी कर रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी आपातकाल के पीड़ित हैं और उन दिनों वे बीजेपी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ थे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में ही उन्होंने छपरा से लोकसभा का चुनाव जीता था। ऐसे में उनके लिए आपातकाल के मुद्दे पर देर तक कांग्रेस का साथ देना आसान नहीं होगा। लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि इस मुद्दे को कांग्रेस उठाए और पीछे से उसका साथ वे देते रहें। इस रणनीति के जरिए उनकी कोशिश है कि बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन से सत्ता छीन लें। लेकिन संघ इस मांग से उस तरह पीछे हटता नहीं दिख रहा, जिस तरह 2015 के चुनावों के दौरान आरक्षण पर आए मोहन भागवत के बयान से उपजे विवाद के चलते पीछे हटता दिखा। कांग्रेस ने अब तक आपातकाल को लेकर अपनी गलती नहीं मानी है। संघ की मांग के चलते यह मुद्दा उछल रहा है। जैसे-जैसे इस मुद्दे की तासीर बढ़ेगी, वैसे-वैसे कांग्रेस के लिए अपना बचाव कर पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि वह कैसे साबित कर पाएगी कि आपातकाल सही था?

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

हरियाणा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिह्नों पर चलते हुए जनसेवा के लिए कर रही कार्य - नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिह्नों पर चलते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने रविवार को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण मिशन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण को दूषित होने से बचाने हेतु महापुरुषों के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और पौधारोपण भी किया। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखर व्यक्तित्व के धनी, जनसंघ संस्थापक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र हित को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए। इसलिए हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चलें और देश को विकसित भारत की ओर ले जाने में अपना योगदान दें।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण

एसवाईएल को लेकर 9 जुलाई को नई दिल्ली में अहम बैठक -मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदैव देश व समाज सेवा को सर्वोपरि समझा और हमेशा गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। इसलिए उन्हें गरीब लोगों का हितैषी माना जाता है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसवाईएल को लेकर 9 जुलाई को नई दिल्ली में अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सर्वसम्मति से सकारात्मक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ हमारा भाईचारा है, इसलिए बैठक में बातचीत से कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जंगल सफारी बनाने को लेकर भी व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। कल ही गुजरात के वनतारा जामनगर का दौरा कर जानकारी ली गई है। वहां लावारिस, घायल पशु-पक्षियों को रेस्क्यू करके इलाज करने के लिए सेंटर बनाया हुआ है। यह केन्द्र उन्हें ऐसे पशु-पक्षियों, जुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षण देकर बचाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत से मिलकर एनसीआर में डिज्नीलैंड बनाने का आग्रह किया है। इसके लिए 500 एकड़ भूमि का चयन भी कर लिया गया है। यह नागरिकों के लिए बहुत ही शानदार और भव्य पर्यटक स्थल के रूप में उभरेगा।

एक नजर

ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से बढ़ रहा पृथ्वी का तापमान, लोगों में जागरूकता बेहद जरूरी : हरविन्द्र कल्याण

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का सामना करना पड़ रहा है। समाज को मिलकर ऐसी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण रविवार को करनाल में महाराजा अग्रसेन भवन में जेसीआई इंडिया जोन 10 गोल्ड मिडकॉन 2025 महोत्सव में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जेसीआई के कार्यक्रमों से उनका पुराना जुड़ाव है। समाज हित में किए जा रहे कार्यों के लिए उन्होंने जेसीआई सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति में समाज अथवा गरीब के लिए कुछ करने का भाव जागृत होता है तो यह उसका उत्थान (राइज अप) है। नेतृत्व के गुण हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन लीडर वही है जो किसी भी चुनौती को पार करने की पहल करे। जेसीआई सदस्य स्वास्थ्य जागरूकता, व्यक्ति निर्माण, पर्यावरण, चिकित्सा शिविरों का आयोजन जैसे क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

हरियाणा के बिजली उपभोक्ता हुए हाईटेक : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

*बोले, 49 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन करते हैं बिल भुगतान

*ग्रामीण बिजली उपभोक्ता भी करते हैं ऑनलाइन माध्यमों का जमकर इस्तेमाल

*म्हारा गांव-जगमग गांव योजना से 5887 गांवों में 24 घंटे

चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा ने बिजली वितरण और उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति कर दी है। आज प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 81 लाख 92 हजार 187 पहुंच गई है, उनमें से 49 लाख 15 हजार 312 उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल माध्यमों से कर रहे हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ हरियाणा की डिजिटल साक्षरता का प्रमाण है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत का भी परिचायक है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री विज ने बताया कि हरियाणा में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली वितरण का जिम्मा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास है। इन दोनों निगमों को हर माह मिलने वाले कुल राजस्व का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त हो रहा है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी उपभोक्ता नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, यूपीआई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भुगतान कर रहे हैं। इससे न सिर्फ बिलिंग प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए लंबी कतारों में लगने की समस्या भी खत्म हो गई है।

उपभोक्ता सेवाओं में डिजिटल क्रांति

श्री अनिल विज ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बिल भुगतान ही नहीं, बल्कि नया कनेक्शन, लोड में वृद्धि/कमी, नाम परिवर्तन, शिकायत निवारण, मीटर स्थानांतरण जैसी सभी सेवाएं भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल रही हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक केंद्रीय ग्राहक सेवा केंद्र, पंचकूला और गुरुग्राम में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हुआ है।

तकनीकी सुधार और स्मार्ट मीटरिंग का प्रयोग

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में तकनीकी सुधारों के तहत शहरी फीडरों पर स्वचालित मीटर रीडिंग लागू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग प्रणाली के जरिए मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ है और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे मानेसर और कुंडली में स्मार्ट ग्रिड प्रणाली का विस्तार किया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति में विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार आया है।

म्हारा गांव-जगमग गांव योजना – ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली

श्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा सरकार की म्हारा गांव-जगमग गांव योजना ने ग्रामीण इलाकों की तस्वीर ही बदल दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 5887 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण उपभोक्ता भी अब डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है।

तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में ऐतिहासिक गिरावट आई

श्री विज ने बताया कि पिछले 13 वर्षों में हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में ऐतिहासिक कमी दर्ज की है। वर्ष 2012-13 में यह हानि 29.31 प्रतिशत थी, जो जनवरी 2025 तक घटकर मात्र 10.52 प्रतिशत रह गई है। HBVN ने 35.60 प्रतिशत से गिरकर 9.38 प्रतिशत और DHBVN ने 23.29 प्रतिशत से घटकर 11.35 प्रतिशत तक की हानि को सीमित किया है। यह उपलब्धि स्मार्ट मीटरिंग, लाइन लॉस नियंत्रण, तकनीकी सुधार और उपभोक्ता जवाबदेही बढ़ाने के कारण संभव हो सकी है।

***ट्रांसफार्मर क्षति दर में ऐतिहासिक गिरावट आई**

उन्होंने बताया कि हरियाणा में ट्रांसफार्मर क्षति दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 1997-98 में यह दर 30.45 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में घटकर 4.74 प्रतिशत रह गई है।

ट्रांसफार्मरों की संख्या 1.46 लाख से बढ़कर 7.08 लाख हो गई है, फिर भी क्षति दर में गिरावट ने बिजली वितरण प्रणाली की मजबूती को सिद्ध किया है। इसका श्रेय नियमित रखरखाव, समय पर मरम्मत, नई तकनीक और बेहतर मॉनिटरिंग को जाता है।

साइबर फ्रॉड – डिजिटल युग की नई चुनौती से निपटने पर बल -विज

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान के बढ़ते चलन के साथ साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई बार उपभोक्ताओं को फर्जी कॉल या लिंक के जरिये ठगा जाता है। इसको लेकर बिजली निगमों के पास शिकायतें आती रहती हैं।

उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और निगमों को सुरक्षा के ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। श्री विज ने कहा कि हरियाणा के बिजली उपभोक्ता अब पूरी तरह हाईटेक हो चुके हैं। डिजिटल सेवाओं, तकनीकी सुधारों और 24 घंटे बिजली आपूर्ति ने प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। आने वाले समय में स्मार्ट तकनीकों और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से यह प्रगति और भी रफ्तार पकड़ेगी।

नरवाना विधानसभा क्षेत्र वासियों के सुझाव और सहयोग को धरातल पर उतारने की रहेगी पूरी कोशिश : कृष्ण कुमार बेदी

चण्डीगढ़।

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि नरवाना के चहुंमुखी विकास के लिए विधानसभा वासियों के सुझाव और सहयोग को धरातल पर उतारने की भरपूर कोशिश की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। श्री कृष्ण कुमार बेदी ने यह बात आज एसडी महिला कॉलेज, नरवाना में स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित निःशुल्क मेडिकल हैल्थ चैकअप कैम्प में सम्बोधित करते हुए कही। निःशुल्क मैडिकल हैल्थ चैकअप कैम्प में 328 लोगों ने हैल्थ चैकअप करवाकर लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि यह कैंप स्थानीय नागरिकों की सेवा में समर्पित एक बेहतरीन पहल है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य जांच की सुविधा का लाभ उठाया। अच्छा स्वास्थ्य समाज की नींव है। ऐसे आयोजन न केवल जन जागरूकता फैलाते हैं, बल्कि आम जनता को समय रहते बीमारियों की पहचान का अवसर भी देते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार आने वाले समय में अधिक से अधिक स्वास्थ्य जांच शिविरों को प्रोत्साहित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाएगी। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वांगीण रूप से सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर है। यह कदम इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुफ्त उपचार, डिजिटल निगरानी, मातृ-शिशु कल्याण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं समुदाय-आधारित पहलों को एकीकृत तरीके से लागू कर रही है। प्रत्येक जिला व मेडिकल कॉलेज में 50-बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक एवं ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय के एक सरकारी अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज निशुल्क उपलब्ध होगा।

इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क, सुरक्षा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से नरवाना विधानसभा क्षेत्र में नए बस स्टैंड, रैस्ट हाउस, और हिसार रोड पर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया जाएगा। पानी निकासी के लिए पाईप लाईन का उद्घाटन सहित अनेक परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा।

प्राकृतिक खेती से तैयार फसल को खरीदने के लिए सरकार ने गुरुग्राम में स्थापित की अनाज मंडी -श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों द्वारा पैदा की फसल को खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में अनाज मंडी तैयार की है। अनाज मंडी में फसल की क्वालिटी चैक करने के लिए एक लैब स्थापित की गई है। लैब में क्वालिटी तय होने के बाद गठित की गई कमेटी द्वारा फसल का भाव तय कर उसको खरीदा जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रविवार को उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र, लाडवा में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने फल केंद्र परिसर में आम का पौधा रोपित किया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बागवानी क्षेत्र के प्रगतिशील 10 किसानों को 5100 रुपए, ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मेले में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर आम की किस्म के बारे में विशेषज्ञ से जानकारियां प्राप्त की। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करके फसलों को तैयार किया जा सके। अब तक 10 हजार एकड़ में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती की जा रही है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में लाडवा में इंडो इजराइल तकनीक के तहत उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र स्थापित किया गया था। इस केंद्र की 10 हजार पौधों से शुरुआत हुई थी, अब प्रतिवर्ष 1 लाख पौधों की पौध किसानों के लिए तैयार की जा रही है। साथ ही आम, लीची, नाशपाती, आड़ू व चीकू सहित छह फसलों पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके फल केंद्र में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा आम का पेड़ तैयार किया जा रहा है, जिसके फल को मार्केट में करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो कीमत मिल सकती है। साथ ही एक पौधे को छह कलमों से तैयार करके छह प्रकार के फल एक ही पेड़ से प्राप्त किया जा रहे हैं। श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और परंपरागत खेती में बदलाव लाने के लिए प्रदेश में ऐसे 17 केंद्र खोले जाने हैं, जिनमें से 11 बनकर तैयार हो चुके हैं। जल्द ही अंबाला में लीची और स्ट्रॉबेरी के लिए यमुनानगर में उप केंद्र स्थापित किया जाएगा।

किसानों के लिए गेहूं और धान की फसल के अलावा बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी व अन्य फसलों को अपनाने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए योजनाएं बना रही है। योजना बनने के बाद किसानों की तरफ से जो समस्या, दिक्कत सामने आती है, उसे उसी हिसाब से योजना में परिवर्तन करके किसानों को लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में किसान महत्वपूर्ण कड़ी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसानों को अपनी परंपरागत खेती में बदलाव करते हुए कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार द्वारा किसानों की फसल का मार्केट में एमएसपी से कम भाव मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत क्षतिपूर्ति की जाती है। किसानों के घाटे को सरकार वहन करती है। उन्होंने कहा कि खन्न से होने वाले गड्ढे का प्रयोग मछली पालने के लिए किया जाएगा। नई योजनाओं से हर वर्ग की आमदनी को बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2027 तक हमारा देश विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बन जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन श्री धर्मवीर मिर्जापुर सहित प्रदेशभर से आए किसान मौजूद रहे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में की शिरकत

किसानों के लिए लाडवा उपकेंद्र में हर वर्ष तैयार की जाती हैं एक लाख पौधों की पौध

सरकार सच्चे अर्थों में कर रही हैं जनहितैषी और अंत्योदय की भावना से कार्य – कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी

चंडीगढ़।

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार सच्चे अर्थों में जनहितैषी सरकार है, अंत्योदय की भावना से प्रत्येक वर्ग का कल्याण करना उनकी प्राथमिकताओं में सुमार है। ग्रामीणों द्वारा उनको जो भरपूर सहयोग मिला है अब उनका ऋण उतारने की बारी मेरी है। ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। किसी भी सूरत में क्षेत्रवासियों का विश्वास नहीं टूटने दिया जाएगा। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों का चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। श्री बेदी शनिवार देर सांय नरवाना (जींद) में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित धन्यवादी दौरे के दौरान बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने तीन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। जिसमें एक करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से बनी गांव की फिरनी का उद्घाटन किया, 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाली वाल्मीकि चौपाल और 13 लाख रुपये से बनने वाली मुस्लिम चौपाल का शिलान्यास भी किया। कैबिनेट मंत्री के सम्मुख ग्राम पंचायत द्वारा कर्मगढ़ से लोन तक की सड़क बनाने, गन्दे पानी की निकासी करवाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने, जलघर का जीर्णोद्धार करने, गलियों का निर्माण करने, जिम का सामान उपलब्ध करवाने, पार्क बनवाने, स्ट्रीट लाईटें लगवाने, बस सेवा शुरू करवाने समेत अन्य मांगें रखीं। जिस पर कैबिनेट मंत्री ने मौके पर ही कर्मगढ़ से लोन तक की सड़क बनाने की घोषणा की। इस सड़क के निर्माण पर लगभग एक करोड़ 54 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार से गांव में बस सेवा शुरू करवाने का काम किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा जो मांगें रखी गई है उनका सम्बन्धित विभागों द्वारा एस्टिमेट तैयार करवाया जाएगा। इन विकास कार्यों को करवाने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्राम पंचायत को गलियों, नालों व अन्य कार्य करवाने के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कर्मगढ़ गांव के विकास को अमलीजामा पहनाने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। श्री बेदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने केन्द्र व राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और लगातार उन्हें जनसेवा का जो मौका दिया इस पर सरकार पूर्णतया खरी उतरेगी। सरकार द्वारा लगातार ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका फायदा सीधा लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। मौजूद राज्य सरकार ने प्रदेश में भाई-भतीजावाद, खर्ची-पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया है, जिसका परिणाम यह है कि आज प्रदेश के युवा अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं वो जो कहते है करके दिखाते भी है। इसलिए आने वाले पांच साल में प्रदेश और अधिक तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग रहेगा।

शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों का होगा चहुमुखी विकास

कर्मगढ़ गांव के विकास के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से विकास परियोजनाओं को पहनाया जाएगा अमलीजामा

हरियाणा के छोरे का चीन में कमालः झटके दो स्वर्ण और एक रजत, पैरा एशियन चैंपियनशिप में लहराया तिरंगा

कैथल।

हरियाणा के पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने चीन के बीजिंग में एक से छह जुलाई 2025 तक आयोजित पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पदक जीते। इनमें दो स्वर्ण और एक रजत पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में एशिया के कई देशों के तीरंदाजों ने हिस्सा लिया।

व्यक्तिगत और मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण

हरविंदर ने व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में थाईलैंड के तीरंदाज नेटॉसरी को 7-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। मिक्स्ड टीम इवेंट में हरियाणा की भावना के साथ जोड़ी बनाकर उन्होंने चीन की टीम को 5-4 से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता। वहीं, पुरुष टीम स्पर्धा में भारतीय टीम को चीन के खिलाफ 4-5 के स्कोर से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा।

कोच ने दी उपलब्धि की जानकारी

हरविंदर के कोच ने बताया कि बीजिंग में आयोजित इस चैंपियनशिप में हरविंदर ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया।

पेरिस पैरालंपिक में रचा था इतिहास

हरविंदर सिंह ने 2024 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। फाइनल में उन्होंने पोलैंड के लुकास सिसजेक को सीधे सेटों में हराया और चार बार लक्ष्य के केंद्र पर सटीक निशाना लगाया। यह उपलब्धि उन्हें भारत का पहला पैरालंपिक तीरंदाजी स्वर्ण पदक विजेता बनाती है।

हरविंदर की उपलब्धि पर गर्व

हरविंदर की इस सफलता ने न केवल कैथल बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी मेहनत और समर्पण युवा तीरंदाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्थानीय निवासियों और खेल प्रेमियों ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की है और भविष्य में भी उनसे ऐसे ही शानदार उपलब्धियों की उम्मीद जताई है।

विनेश के गृह जिला दादरी में सम्मानित हुए बृजभूषण शरण सिंह, धरी रह गई खापों और पंचायतों की विरोध धमकी

दादरी। कुश्ती की पूर्व खिलाड़ी विनेश फोगाट के गृह जिला में पहुंचकर रविवार को डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सम्मान प्राप्त किया। दूसरी ओर दो दिन से जिला की खापों व पंचायतों की ओर से बृजभूषण के आगमन का विरोध करने और दादरी में एंट्री न देने के प्रेस नोट जारी करने वाली खापों व पंचायतों की धमकी और बयान धरे गए। रविवार को बौंदकलां में पहलवान रचना परमार की सफलता पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, विधायक सुनील सांगवान, सांसद धर्मबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं, अंतरराष्ट्रीय पहलवान और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त भी पहुंचे हैं। हालांकि विधायक और सांसद समय के अभाव का हवाला देकर बृजभूषण के आने से पहले ही निकल गए। उन्होंने भी बृजभूषण से मिलने से दूरी बनाई। दो दिन पहले तक विरोध के बयानबाजी कर रहे खाप नेताओं की जुबान भी सिमट गई और किसी खाप ने आगे आने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। उनकी विरोध भरी बातें केवल हवा में उड़कर रह गईं। कार्यक्रम की शुरुआत रविवार सुबह 11:30 बजे हुई। इससे पहले गांव में रचना परमार को गाड़ी में बैठाकर एक विजय यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में सांसद धर्मबीर सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कम भीड़ को देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने घोषणा की कि बलाली खेल स्टेडियम में 21 लाख रुपये की लागत से सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने रचना परमार को स्वर्ण पदक की उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। रचना ने फाइनल में जापान की खिलाड़ी को 9-0 से हराकर यह स्वर्ण पदक हासिल किया था। हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह के दौरे को लेकर किसान यूनियनों और खाप पंचायतों ने पहले विरोध की घोषणा की थी, लेकिन समारोह के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। समारोह में विधायक सुनील भी मौजूद रहे और उन्होंने रचना को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। पूर्व सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पुलिस सुरक्षा के बीच स्टेज से उतरकर ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल पूछा, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। उनके साथ मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी समारोह में शिरकत की।

18 जनवरी 2023 को विनेश, साक्षी और बजरंग पूनिया ने दिल्ली जंतर-मंतर पर बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए।

इसके बाद 23 जनवरी को विनेश ने यौन शोषण का आरोप लगाया। तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मिलकर मामले की जांच की।

शिवराज-खट्टर समेत 6 चेहरे भाजपा अध्यक्ष की रेस में

नई दिल्ली।

भाजपा जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी ह्यू के मुताबिक, भाजपा नए अध्यक्ष के लिए 6 नामों पर विचार कर रही है, इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। वहीं, भाजपा महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी रेस में बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए

संगठनात्मक अनुभव के साथ जातीय-क्षेत्रीय समीकरण देखे जा रहे; केंद्रीय चुनाव समिति का गठन जल्द

तीन मुख्य बातों-संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण को ध्यान में रख रही है। जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक केंद्रीय चुनाव समिति का गठन हो सकता है। यदि चुनाव की जरूरत पड़ती है तो यह समिति नामांकन, जांच और मतदान की प्रक्रिया पूरी करेगी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन पर हैं। वहीं, वह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, इस वजह से भाजपा जल्द नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी है। पार्टी संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 50 फीसदी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद ही होता है। फिलहाल भाजपा की 37 मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिट हैं। इनमें से 26 राज्यों में अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। भाजपा ने जुलाई के शुरुआत 2 दिन में 9 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने। इसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। पार्टी ने 1-2 जुलाई को 9 राज्यों (हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन दीव और लद्दाख) में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव किया।

चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

नई दिल्ली।

साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। अब एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान ने बीजेपी और जेडीयू दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम से चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान रविवार को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में पार्टी द्वारा आयोजित नव-संकल्प महासभा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने हुंकार भरते हुए कहा, आज सारण की इस पावन धरती से, आप सबके सामने मैं यह कहकर जा रहा हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव

लड़ूंगा बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो सही मायनों में प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएगा।

चिराग पासवान शेर का बेटा है, डरने वाला नहीं

लोजपा-आर प्रमुख ने इस दौरान

बिहार चुनाव से पहले एनडीए में घमासान

अपनी मजबूती और दृढ़ संकल्प भी दिखाया। उन्होंने कहा, मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया और जो लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग यह सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वे लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, राम विलास पासवान का बेटा है। उन्होंने आगे कहा, मैं ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पर कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए साथियों जरूरत है मुझे आप सब की।

मुझे बिहार आने से रोकने की कोशिश

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिहारी युवाओं को पलायन कर दूसरे राज्यों और देशों में रहने के लिए मजबूर किया, वे उसी तरीके से चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गए तो युवाओं को उनका हक दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और मजदूरों के हक की बात करेंगे, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आएं। चिराग ने आरोप लगाया कि यही वजह है कि ये लोग षड्यंत्र रचते हैं और भ्रम की स्थिति बनाते हुए बार-बार यह सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।

सुपरपावर देशों की तानाशाही से टकराव का माहौल, नितिन गडकरी बोले- कभी भी हो सकता है विश्व युद्ध

नागपुर। (बेबवार्ता) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि दुनिया में रूस-यूक्रेन और इस्राइल-ईरान जैसे युद्धों के कारण टकराव का माहौल बन गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति बन रही है जिससे कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में बियॉन्ड बॉर्डर्स नाम के पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी महाशक्तियों की तानाशाही और अधिनायकवाद के चलते दुनिया से समन्वय, सौहार्द और प्रेम खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया में संघर्ष का वातावरण है। रूस-यूक्रेन और इस्राइल-ईरान के बीच युद्ध जारी है। ऐसे हालात बन रहे हैं कि कभी भी वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की धरती है, जिसने दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि युद्ध की तकनीक अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब टैंक और पारंपरिक विमान कम उपयोगी हो गए हैं, जबकि मिसाइल और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा अब मिसाइलें सीधे नागरिक बस्तियों पर गिराई जा रही हैं, जिससे मानवता की रक्षा करना मुश्किल होता जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर वैश्विक

बिहार भारत की अपराध राजधानी बन गया - राहुल गांधी

पटना।

बिहार की राजधानी पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। इस घटना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सरकार पर तीखा निशाना साधा है और दावा किया है कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने बिहार को भारत की अपराध राजधानी बना दिया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, आज बिहार लूट, गोलीबारी और हत्या के साये में जी रहा है। अपराध आम बात हो गई है और सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। कांग्रेस सांसद ने बिहार के लोगों से अपील की कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में ऐसी सरकार को वोट न दें जो आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने आगे

लिखा, हर हत्या, हर डकैती, हर गोली बदलाव की पुकार है। एक नए बिहार का समय आ गया है - डर का नहीं प्रगति का। इस बार आपका वोट सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं है - यह बिहार को बचाने के लिए है।

तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने भी साधा निशाना

राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, यह एक भयानक घटना है। व्यवसायी बिहार छोड़ना चाहते हैं। यह घटना पटना के बीचों-बीच हुई... फिर भी पुलिस को यहां पहुंचने में दो घंटे लग गए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, छह साल पहले उनके (गोपाल खेमका) बेटे की हत्या कर दी गई थी और हत्यारों में से कोई भी पकड़ा नहीं गया... जब तक रिश्वत के जरिए तबादले और पोस्टिंग की जाती है और काम करने वालों की पोस्टिंग नहीं की जाती तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है... सीएम बेहोश है और थके हुए हैं अधिकारी सरकार चला रहे हैं। घटना के सामने आने के तुरंत बाद बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचे और सवाल उठाया कि ऐसे इलाके में ऐसी घटना कैसे हो सकती है जहां जिला मजिस्ट्रेट सहित सभी प्रमुख अधिकारी रहते हैं। उन्होंने आगे पूछा कि क्या बिहार सरकार खेमका परिवार के सभी सदस्यों को मरते देखना चाहती है। गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष इस मुद्दे को आगामी चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश करेगा।

मुंबई में हिंदुओं को भाषा के कारण पीटा

बीजेपी नेता आशीष शेलार ने पहलगाम हमले से की थप्पड़कांड की तुलना

मुंबई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। वहीं, अब महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने मराठी भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी है। आशीष शेलार का कहना है कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया था और महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर हमले किए जा रहे हैं। यह बेहद निराशाजनक है।

एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार रहा: आशीष शेलार

आशीष शेलार का कहना है कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी न सिर्फ मराठी लोगों की बल्कि गैर-मराठी लोगों की भी रक्षा करेगी। आशीष शेलार के अनुसार, मराठी हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में लोगों से उनका धर्म पूछा गया और गोली मार दी गई। महाराष्ट्र में लोगों पर भाषा को आधार बनाकर हमले किए जा रहे हैं। एक हिंदू के द्वारा दूसरे हिंदू को पिटता हुआ देखकर इन नेताओं को मजा आ रहा है। बता दें कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी को लेकर राज्य में मुहिम छेड़ रखी है। हाल ही में एमएनएस कार्यकर्ताओं को मराठी न बोलने की वजह से एक दुकानदार को थप्पड़ मारते देखा गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसी बीच मशहूर बिजनेसमैन सुशील केडिया ने बयान दे दिया कि वो 30 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उन्हें मराठी नहीं आती है। उन्होंने राज ठाकरे को टैग करते हुए लिखा मैं मराठी नहीं सीखूंगा। बोलो क्या करना है सुशील केडिया की इस पोस्ट से बौखलाए मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर पर हमला कर दिया और जमकर ईंट-पत्थर बरसाए थे।

बाइक में टक्कर मारकर ट्रक में जा घुसी कार, चार लोगों की मौत

गाजीपुर। शहर कोतवाली के वाराणसी-गोरखपुर नेशनल हाईवे पर रसूलपुर गांव के पास बनाए गए कट के पास एक्सयूवी कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। कार ने पहले बाइक और फिर ट्रक में धक्का मारा, जिससे बाइक सवार शहर कोतवाली के नसीरपुर गांव निवासी 70 वर्षीय चन्द्रज्योति पाल, दो वर्षीय नतिनी अस्मिता पाल व चंद्रज्योति के बहन का 30 वर्षीय पुत्र संजीव पाल की मौत हो गई। वहीं, नंदगंज के बासुचक निवासी कुंती पाल गंभीर रूप से घायल हो गई। चन्द्रज्योति की बेटी 45 वर्षीय कुंती पाल की भी इलाज के लिए वाराणसी ले जाते समय रस्ते में मौत हो गई। पुलिस कार चालक को हिरासत में ले ली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक पर एक युवक, दो महिला व एक बच्ची सवार थी।

उद्धव-राज की रैली पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- यह विजय रैली नहीं बल्कि 'रुदाली सभा' थी, मराठी भाषा की हुई अनदेखी

मुंबई। मुंबई में हुई विजय रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे और शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे लगभग 18 वर्षों बाद एक साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। राज ठाकरे ने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा कि जो काम शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे नहीं कर पाए, वह फडणवीस ने कर दिखाया और दोनों ठाकरे भाइयों को एक कर दिया। इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं राज ठाकरे का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे दोनों ठाकरे भाइयों को जोड़ने का श्रेय दिया, वह मेरे

लिए बालासाहेब का आशीर्वाद जैसा है। लेकिन जो सभा हुई, वह विजय रैली नहीं बल्कि रुदाली सभा थी। उसमें मराठी भाषा का जिक्र तक नहीं था, सिर्फ सत्ता की लालसा और शिकायतें थीं।

मोदी सरकार के नेतृत्व में हुए बेहतरीन काम

फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 25 सालों से शिवसेना मुंबई नगर निगम पर शासन कर रही थी, लेकिन उन्होंने मराठी समुदाय के लिए कुछ खास नहीं किया। इसके विपरीत, मोदी सरकार के नेतृत्व में उन्होंने मुंबई के बीडीडी चॉल, पात्रा चॉल और अभ्युदय नगर में मराठी परिवारों को बेहतर घर मुहैया कराए, जिससे मराठी समुदाय को मजबूती मिली है। यह बात शिवसेना को नागवार गुजरी है।

अपने हिंदुत्व पर गर्व

मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर 'मराठी अस्मिता' और 'हिंदुत्व' की बहस गरमाने लगी है। फडणवीस ने कहा, "हम मराठी हैं और अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही हम हिंदू भी हैं और अपने हिंदुत्व पर भी उतना ही गर्व करते हैं। हमारा हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने वाला है। यह बयान आगामी चुनाव में भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें हिंदुत्व कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

केंद्र की मौजूदगी में पंजाब-हरियाणा होंगे आमने-सामने, 9 जुलाई को दिल्ली में सीएम मान व सैनी रखेंगे अपना पक्ष

चंडीगढ़। सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद पर एक बार फिर पंजाब और हरियाणा आमने-सामने होंगे। केंद्र की मध्यस्थता में 9 जुलाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एसवाईएल के मुद्दे पर अपने राज्यों की ओर से पक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि एसवाईएल विवाद का कोई हल निकाला जाए। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में होगी। बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 13 अगस्त को एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र एसवाईएल विवाद पर पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति बनाने के प्रयास में जुट गया है। पंजाब-हरियाणा के बीच

एसवाईएल के अलावा भी कई बार जल विवाद देखने को मिल चुका है। चाहे फिर बात बीते दिनों नंगल डैम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की मांग पर खड़े हुए विवाद से ही क्यों न जुड़ी हो। पंजाब के मुख्यमंत्री मान सतलुज-यमुना लिंक नहर पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब के पास किसी भी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। राज्य में 153 में से 115 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। जहां भूजल स्तर 400 से 600 फुट नीचे चला गया है। सीएम मान एसवाईएल के मुद्दे पर कई बार सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि यमुना का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, जोकि हरियाणा से यूपी से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जा रहा है। एसवाईएल विवाद की जड़ 31 दिसंबर, 1981 के उस समझौते में है, जिसके तहत एसवाईएल नहर की योजना बनी थी और 1982 में निर्माण शुरू हुआ था। हालांकि 1990 में काम बंद हो गया। हरियाणा ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने 2002 में पंजाब को एक साल में नहर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। 2004 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि यदि पंजाब निर्माण नहीं करता, तो केंद्र इसे अपने हाथों में ले। कैप्टन सरकार ने 2004 में जल समझौते रद्द कर दिए और 2016 में अकाली-भाजपा सरकार ने नहर के लिए अधिग्रहीत जमीन को डिनोटिफाई कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर का विकास डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों की विजय : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्क रोड पर सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी पावन स्मृतियों को याद किया।लखनऊ में सिविल अस्पताल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को खत्म करके डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार आज किया है। उन्होंने कश्मीर को भारत के संविधान के अनुरूप शेष भारत

के साथ जोड़ने का काम किया गया है। आज जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों की विजय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म छह जुलाई 1901 में हुआ था। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी सेवाएं दी थी। वह एक प्रखर वक्ता के साथ ही महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरा जीवन राष्ट्रमाता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। बंगाल में अकाल के दौरान उनकी सेवाओं को पूरा देश याद करता है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन सरकार के जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करने और परमिट सिस्टम का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के भीतर नए इंवेस्टमेंट के रूप में नया डेस्टिनेशन स्थापित हुआ है। मुखर्जी ने खाद्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में भारत के भीतर खाद्य की आत्मनिर्भरता और देश के औद्योगिकरण की जो नींव रखी थी, वह नए भारत में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कोविड में अस्सी करोड़ लोगों को अनाज वितरण करना उसी की एक मिसाल है। जो आज भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है।

लोगों की आस्था का सागर है कांवड़ यात्रा, इस पर घटिया बयानबाजी न करें अखिलेश : केशव प्रसाद

मेरठ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ-साथ विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। कहा कि सपा समेत विपक्षी दलों के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि वह कांवड़ यात्रा को लेकर घटिया बयान बाजी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का सागर है। इस पर बयानबाजी से अखिलेश यादव बाज आएं। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन अब जनता समझ गई है। 2027 में उप्र में सपा का कथित पीडीए पीडीए (पिछड़ा दलित

अल्पसंख्यक) फ्लाप साबित होगा। अखिलेश यादव का सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद मेरठ सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। कहा कि भाजपा सुशासन, विकास, सभी की सुरक्षा के मुद्दे पर 2027 का चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में हम 2017 के परिणाम को दोहराएंगे। देशभर में भाजपा को जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इसके उदाहरण हैं। अब बिहार में भी भाजपा जदयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार के साथ बहुमत प्राप्त करने वाली है। कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी से कांवड़ यात्रा हो या फिर अन्य धार्मिक कार्यक्रम और त्योहार। सभी का आयोजन सुरक्षित और बेहतर माहौल में कराया जा रहा है। फिर भी अखिलेश यादव साधु संतो और कथावाचकों पर टिप्पणी कर रहे हैं। समाज उन्हें इसका जवाब देगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ताजिया की ऊंचाई को लेकर लोगों को खुद समझना चाहिए। त्योहार मनाने में सरकार उनके साथ है, लेकिन अव्यवस्था नहीं करने दी जाएगी। कांवड़ मार्गों के रेस्टोरेंट के मालिक नाम बदलकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट है। धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। हरिद्वार मार्ग पर तो 12 महीने श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है।

कैब ड्राइवर्स की हत्या कर, लाश खाई में फेंक देता था... दिल्ली से सीरियल किलर गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली से पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सीरियल किलर अपने तीन साथियों के साथ मिलकर कैब ड्राइवर्स की हत्या कर लाश खाई में फेंक देता था. इसकी गिरफ्तारी से चार कैब ड्राइवर्स की हत्या का पर्दाफाश है. पुलिस को शक दर्जनों मिसिंग कैब ड्राइवर्स की हत्या को भी इस सीरियल किलर ने अपने गैंग के साथ अंजाम दिया है. सीरियल किलर और उसके तीन साथी रेंट पर कैब बुक करते थे फिर उत्तराखंड की पहाड़ियों में कैब ड्राइवर को पहले बेहोश करते थे. फिर उसका गला दबाकर हत्या कर लाश को उत्तराखंड के पहाड़ों से गहरी खाई में फेंक देते थे. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने लगभग 25 साल से फरार चल रहे इस खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय लांबा उर्फ बंसी के रूप में हुई है, जो दिल्ली और उत्तराखंड में डकैती के दौरान हत्या के 4 मामलों में वांटेड था. पुलिस ने उसे घोषित भगोड़ा घोषित कर रखा था.

टैक्सी ड्राइवरों को बनाया था निशाना

पुलिस के मुताबिक अजय साल 2001 से अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाता था. ये लोग टैक्सी किराए पर लेकर सुनसान इलाकों में ले जाते, फिर ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी लूट लेते और शव को पहाड़ी इलाकों में फेंक देते, ताकि कोई सबूत न बचे. लूटी गई गाड़ियां नेपाल में बेच दी जाती थीं.

अजय का आपराधिक इतिहास

अजय मूल रूप से दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके का रहने वाला है और 1976 में पैदा हुआ था. उसने छठी क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया और किशोर अवस्था में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया. विकासपुरी थाने में वह बंसी के नाम से घोषित बदमाश था. 1996 में उसने नाम बदलकर अजय लांबा कर लिया और बरेली, उत्तर प्रदेश में बस गया. वह 1999 से 2001 के बीच दर्ज चार हत्या-डकैती के मामलों में आरोपी था. ये केस दिल्ली के न्यू अशोक नगर, उत्तराखंड के हल्द्वानी, अल्मोड़ा और चंपावत में दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उस पर 1990 से पहले के कई चोरी, हथियार रखने जैसे मामले भी दर्ज हैं.

नेपाल में रहा, गांजा तस्करी में भी जुड़ा

पुलिस टीम ने कई महीनों की मैन्युअल और तकनीकी निगरानी के बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अजय 2008 से 2018 तक नेपाल में रहा. इसके बाद वह देहरादून आ गया और परिवार के साथ रहने लगा. साल 2020 से वह उड़ीसा से दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह से जुड़ गया. 2021 में NDPS एक्ट के तहत ब्रह्मपुर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ और 2024 में उड़ीसा के बेरहामपुर में एक ज्वेलरी शॉप डकैती के मामले में भी उसे गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों मामलों में वह जमानत पर बाहर था, लेकिन किसी को अपनी असली पहचान और भगोड़े होने की बात नहीं बताई. फिलहाल पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है और केस की गहराई से जांच की जा रही है.